बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 104 ● नई दिल्ली ● सोमवार 02 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में ई-रिक्शा में जा रही युवती से मोबाइल छीना, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर आरोपी को दबोचा

बाहरी दिल्ली। आजादपुर मंडी से आजादपुर मेट्रो स्टेशन की ओर ई-रिक्शा से जा रही युवती से मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है। मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर झपटमारों की पहचान की और एक आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित से युवती से छीना मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि इस संबंध में बहादुरगढ़ (हरियाणा) के धर्म विहार की रहने वाली इंद्रजीत नांदल की शिकायत पर पर विशेष टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण और खुफिया सूचना के आधार पर कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई।

बजट 2026-27 पर अमित शाह का बड़ा बयान, ये विकसित भारत का गोल्डन रोडमैप है

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप बताया और अगले 25 वर्षों के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए। एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि बजट यह दर्शाता है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार का दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि बजट समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक खाका प्रस्तुत करता है, साथ ही हर कदम पर उनका समर्थन करने के लिए एक व्यावहारिक और ठोस दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में अपना नौवां बजट पेश करने के तुरंत बाद शाह ने ये विचार व्यक्त किए। हालांकि कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सीतारमण ने 1 अप्रैल, 2026 से नए कर अधिनियम को लागू करने की घोषणा की। भारत के इतिहास में यह पहली बार था कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया। शाह ने ङ्क पर पोस्ट किया कि केंद्रीय बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की एक दृढ़ प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए

एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि हर कदम पर उनका समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण भी सामने रखता है। विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण की परिकल्पना करता है जो हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करे। पोस्ट में आगे लिखा गया कि विनिर्माण से लेकर अवसंरचना तक, स्वास्थ्य सेवा से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण विकास से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, और खेल से लेकर तीर्थ स्थलों तक, विकसित भारत बजट हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को साकार करने में मदद करता है। हर भारतीय की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक बधाई, जिन्होंने 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का खाका तैयार करने वाला और अगले 25 वर्षों के लिए दिशा-निर्देश देने वाला बजट प्रस्तुत किया है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और यह तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। मंत्रालय के अनुसार, पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना है; दूसरा कर्तव्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त भागीदार बन सकें; तीसरा कर्तव्य, सबका साथ, सबका विकास की परिकल्पना के अनुरूप, यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग को संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। गैर-ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ रुपये और 53.5 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

हाईस्पीड रेल कॉरिडोर से दिल्ली बनेगी विकास की धुरी, बजट 2026 पर सीएम रेखा गुप्ता ने की केंद्र सरकार की तारीफ

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने बजट पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया है एक्स पर पस्ट में उन्होंने लिखा की बजट की जितनी भी सराहना की जाए, कम है। इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सीएम गुप्ता ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की ठोस कार्ययोजना है। उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश को प्रोत्साहन देने को देश को आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल रेल परियोजना नहीं, बल्कि गति, प्रगति और जनविश्वास का सशक्त प्रतीक है।

उनके अनुसार, इस परियोजना से दिल्ली की कनेक्टिविटी नए स्तर पर पहुंचेगी। यात्रा समय कम होगा, व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूती मिलेगी। सीएम ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली राष्ट्रीय विकास की धुरी के रूप में और अधिक सशक्त होकर उभरेगी।

हाईस्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ने के बाद दिल्ली को कई फायदे

तेज और समयबद्ध यात्रा

युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर

व्यापार के लिए बड़े बाजारों तक आसान पहुंच । पर्यटन गतिविधियों में वृद्धिमजबूत क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी

तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट

सीएम रेखा गुप्ता ने बजट को युवा शक्ति से प्रेरित और तीन प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित बताया। पहला, आर्थिक वृद्धि को गति देना। निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत आधार देकर विकास को स्थायी और व्यापक बनाने पर जोर है। दूसरा, जनता की उम्मीदों को पूरा करना। आम नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए सुविधाएं और अवसर बढ़ाए गए हैं। तीसरा, सबका साथ, सबका विकास। यह सुनिश्चित किया गया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आगे उन्होंने कहा कि, यह बजट केवल आज की जरूरतों का समाधान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत की मजबूत नींव है।

इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री ने बजट में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का आवंटन बढ़ाकर ?12.2 लाख करोड़ किए जाने को बड़ा और निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन नेटवर्क के विस्तार और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को नई गति मिलेगी।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, यलो अलर्ट के बीच जानें कब मिलेगी राहत

नई दिल्ली । पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार देर रात हुई बारिश और हल्की हवाओं ने राजधानी और आसपास के इलाकों में ठंडक को और बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। रविवार सुबह भी रुक रुककर बारिश देखी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार, यह मौसमी हलचल अभी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, 1 से 7 फरवरी के बीच दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इन विक्षोभों का प्रभाव न केवल मैदानी इलाकों में बारिश के रूप में दिखेगा, बल्कि हिमालयी राज्यों में बर्फबारी की भी उम्मीद है। पहले दो पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 3 फरवरी तक अपना असर दिखाएंगे, जबकि तीसरा विक्षोभ 5 फरवरी से सक्रिय होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। शनिवार देर रात दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में रुक-रुककर गरज के साथ बारिश देखने को मिली है। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई है, जिससे रात के समय वाहन चालकों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया है। मौसम विभाग ने पहले तीन दिन बारिश की संभावना जताई थी लेकिन अब रविवार तक ही बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा बीते साल की तुलना में जनवरी 2026 अधिक ठंडा रहा। औसतन अधिकतम तापमान 20.1 और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं, साल 2025 में 21.1 और 8.5 रहा था। मौसम विभाग के अनुसार, पहली फरवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद दिल्ली में दो फरवरी को यह 11 से 13 डिग्री, तीन फरवरी को 10 से 12 डिग्री और 4 फरवरी को 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिल्ली में 5 और 6 फरवरी को न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में 4 से लेकर 6 फरवरी तक 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में सर्द हवाएं चलेंगी।

भविष्य की रफ्तार के लिए दिल्ली हो रही तैयार : टर्मिनल-1 तक सीधी मेट्रो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आधार

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन के विस्तार के साथ ही दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन को मल्टी-लाइन इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद यात्रियों को आईजीआई एयरपोर्ट के सभी टर्मिनलों तक तेज, सीधा और आसान मेट्रो कनेक्शन मिलेगा। गोल्डन लाइन फिलहाल तुगलकाबाद से दिल्ली एरोसिटी तक बनाई जा रही है, जिसका 80 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। अब इस कॉरिडोर को एक ओर कालिंदी कुंज तक एलिवेटेड रूप में बढ़ाया जाएगा, जबकि दूसरी ओर एरोसिटी से आगे आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 तक विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके बाद कालिंदी कुंज, तुगलकाबाद और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों से टर्मिनल-1 तक बिना लाइन बदले मेट्रो से पहुंचना संभव हो सकेगा। इस विस्तार से यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मौजूदा जटिल रूट्स से छुटकारा मिलेगा। अभी दक्षिणी दिल्ली या नोएडा से टर्मिनल-1 पहुंचने के लिए यात्रियों को ब्लू, वॉयलेट या मैजेंटा लाइन के बीच कई बार मेट्रो बदलनी पड़ती है। कुछ रूट्स पर यात्रियों को स्टेशन बदलने के लिए पैदल चलना भी पड़ता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते हैं।

गोल्डन लाइन के विस्तार के बाद यह सफर कहीं यादा सीधा और समय बचाने वाला हो जाएगा। गोल्डन लाइन के तहत एरोसिटी पर बनने वाला नया इंटरचेंज स्टेशन करीब 290 मीटर लंबा होगा, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में अब तक का सबसे लंबा स्टेशन होगा। सामान्य इंटरचेंज स्टेशन की तुलना में यह कहीं अधिक बड़ा होगा, ताकि बढ़ती यात्री संख्या और एयरपोर्ट ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सके। डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार, इस मल्टी-लाइन कनेक्टिविटी से न सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा, बल्कि दक्षिणी दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद से आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों का सफर भी तेज और सुगम होगा।

प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म मिलेगी कनेक्टिविटी

एरोसिटी स्टेशन पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, गोल्डन लाइन और मैजेंटा लाइन का आपसी जुड़ाव यात्रियों के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। यहां प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म और कन्कोर्स-टू-कन्कोर्स कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे बिना स्टेशन से बाहर निकले लाइन बदलना संभव होगा। यही नहीं, भविष्य में यहां एनसीआरटीसी के दिल्ली-अलवर कॉरिडोर को जोड़ने की भी तैयारी है, जिससे यह स्टेशन ट्रिपल इंटरचेंज हब बन सकता है।

एचआईवी से बचाव के लिए एआई से खोजी दवा, दुष्प्रभाव से तबीयत बिगड़ी तो मरीज पहुंचा अस्पताल; हालत गंभीर

नई दिल्ली ।दिल्ली में एचआईवी संक्रमण से बचाव के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से दवा लेने का मामला सामने आया है। दवा के दुष्प्रभाव से मरीज की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे आनन-फानन में राजधानी के एक नामी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरानी की बात यह है कि मरीज ने बिना चिकित्सकीय सलाह के एआई से दवा संबंधी जानकारी जुटाई और एक केमिस्ट से दवा खरीदकर स्वयं उपचार शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार का ड्रग कंट्रोल विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने मरीज से संबंधित केमिस्ट की जानकारी जुटाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना की पुष्टि विभाग के अधिकारियों ने भी की है मिली जानकारी के अनुसार, मरीज ने हाई-रिस्क यौन संबंध बनाने के बाद एचआईवी से बचाव के लिए एआई की मदद से दवा की जानकारी हासिल की और संक्रमण से बचाव के लिए 28 दिन का कोर्स शुरू कर दिया। कोर्स शुरू करने के करीब एक सप्ताह बाद मरीज में दवा के गंभीर दुष्प्रभाव सामने आने लगे। उसे आंखों और त्वचा से जुड़ी समस्याएं होने लगीं, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान मरीज को स्टीवंस-जॉनसन सिंड्रोम से पीड़ित पाया गया। डॉक्टरों के अनुसार यह एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत गंभीर बीमारी है, जो आमतौर पर दवा से होने वाली एलर्जी या संक्रमण के कारण होती है। यह फ्लू जैसे लक्षणों के साथ शुरू होता है। जिसके बाद दर्दनाक दाने, छाले और त्वचा का छिलना शुरू हो जाता है। यह एक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति है जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। देश में एड्स से होने वाली मौतों में करीब 80 फीसदी तक गिरावट आई है। नए मामलों में भी करीब 48 फीसदी तक गिरावट दर्ज हुई है। प्रमुख मेडिकल संस्थानों के अध्ययन में ये बात सामने आई है। देश में 2010 के मुकाबले एड्स से होने वाली मौतों में करीब 80 फीसदी की कमी आई है। नए संक्रमण के मामलों में भी 48 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एम्स और आईसीएमआर के डॉक्टरों द्वारा की गई इस रिसर्च में ये पता चला है। जांच कराओ और तुरंत इलाज शुरू करो नीति ने एड्स को बड़ी हद तक पीछे धकेला है। सही समय पर इलाज मिलने से संक्रमित लोग अब सामान्य जीवन जी पा रहे हैं।

समय पर इलाज से उम्र बढ़ी

समय पर उपलब्ध दवाओं की मदद से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है और लंबी, स्वस्थ जिंदगी जी सकता है।

दुनिया में मची हलचल

भारत और वेनेजुएला के बीच कूटनीति ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई टेलीफोन वार्ता ने वैश्विक ऊर्जा राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस वार्ता का सीधा संबंध तेल से है और इसका परोक्ष असर भारत रूस निर्भरता घटाने, अमेरिका से व्यापारिक दबाव कम करने और ग्लोबल साउथ में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करने से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने भारत को संकेत दिया है कि वह शीघ्र ही वेनेजुएला से तेल खरीद दोबारा शुरू कर सकता है ताकि रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता घटे। यह पहल भारत अमेरिका ऊर्जा संबंधों को नए सांचे में ढालने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है। रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले महीनों में भारत रूसी तेल आयात में प्रतिदिन कई लाख बैरल की कटौती कर सकता है। इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि में डेल्सी रोड्रिगेज ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता के बाद ऊर्जा सहयोग पर सहमति की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक संदेश में कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय साझेदारी को सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की साझा दृष्टि रखते हैं। हम आपको बता दें कि यह वार्ता ऐसे समय हुई है जब वेनेजुएला ने अपने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है। दशकों तक कठोर सरकारी नियंत्रण के बाद अब कानूनों में व्यापक सुधार किए गए हैं। खोज, उत्पादन, वितरण और विपणन में निजी भागीदारी की अनुमति दी गई है। कर और रॉयल्टी घटाई गई है, बड़े प्रोजेक्ट के लिए शुल्क और कम किए जा सकते हैं और विवादों में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता खोला गया है। इस तरह यह बदलाव कर पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के दौर की राष्ट्रीयकरण नीति को पलट दिया गया है। अमेरिका ने भी जवाबी कदम उठाते हुए वेनेजुएला को प्रतिबंधों में ढील दी है। नया सामान्य लाइसेंस अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के तेल के निर्यात, भंडारण, परिवहन और परिशोधन की अनुमति देता है, हालांकि भुगतान और कुछ देशों से जुड़े लेन-देन पर सख्त शर्तें रखी गई हैं। हम आपको याद दिला दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मार्च में वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाया था, जिसमें भारत भी शामिल था। अब दिशा बदली है। देखा जाये तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अवसर का लाभ उठाते हुए सस्ता रूसी तेल बड़ी मात्रा में खरीदा। इससे देश की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हुईं और कीमतों पर भी नियंत्रण रहा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका का दबाव बढ़ा है, व्यापार शुल्क भारी हुए हैं और प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति व्यवस्था जटिल हो गई है। इसी वजह से भारत अब तेल आयात के नए विकल्प तलाश रहा है। आयात के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में रूस से तेल खरीद दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके साथ ही ओपेक देशों से आने वाले तेल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। कई भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल से दूरी बना ली है और आपूर्ति स्रोत बदलने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच, वेनेजुएला के नए कानून ने एक नई संभावना खोली है। उत्पादन और निर्यात में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधों के चलते जो तेल पहले मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचना पड़ता था, अब वह बेहतर कीमत और कम लागत के साथ खुले बाजार में उपलब्ध होगा। सरकारी आकलन के अनुसार, वेनेजुएला में इस साल उत्पादन में 18 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है, जबकि निजी अनुमान इससे भी तेज उछाल की ओर संकेत कर रहे हैं। देखा जाये तो मोदी और रोड्रिगेज की बातचीत सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि सामरिक संकेत है। भारत साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि वह किसी एक स्रोत या किसी एक धड़े के साथ नहीं रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत की आर्थिक संप्रभुता की रीढ़ है और इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए बहुध्रुवीय नीति अनिवार्य है। वेनेजुएला के दरवाजे खुलना भारत के लिए अवसर की तरह है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार तक पहुंच सस्ती और स्थिर आपूर्ति का रास्ता खोल सकती है। हालांकि भारत को अमेरिकी शर्तों, भुगतान नियमों और भू-राजनीति की रस्साकशी में संतुलन भी साधना होगा। सामरिक रूप से यह कदम रूस पर निर्भरता घटाकर भारत की सौदेबाजी की शक्ति को और बढ़ाता है। यदि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करता है तो अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम हो सकता है, साथ ही लैटिन अमेरिका में भारत की मौजूदगी मजबूत होगी। ग्लोबल साउथ के मंच पर भी यह संकेत जाएगा कि भारत ठोस साझेदारी करता है। वहीं वेनेजुएला ने नियम सरल कर यह दिखा दिया है कि आर्थिक यथार्थ विचारधारात्मक जिद से बड़ा होता है। निजी निवेश, कम कर, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और पारदर्शिता से ही उत्पादन बढ़ेगा और आम नागरिक तक लाभ पहुंचेगा। भारत यदि यहां निवेश और दीर्घकालिक खरीद समझौते करता है तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। बहरहाल, इस पूरी तस्वीर के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल और दूरदर्शी विदेश नीति साफ दिखाई देती है।

कच्चे तेल की खरीद और आपूर्ति के मोर्चे पर उन्होंने खुद को एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया है। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल संकट में जूझ रही थी, तब भारत पर भी हर तरफ से दबाव था कि वह सस्ते रूसी तेल से दूरी बनाए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए बहुस्तरीय कूटनीति अपनाई। रूस से तेल खरीद जारी रखी, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से आपूर्ति संतुलित की और अब लैटिन अमेरिका की ओर रणनीतिक कदम बढ़ा दिये हैं। इसी संतुलित नीति का नतीजा रहा कि जहां यूरोप और अमेरिका में ईंधन के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में रहीं। यह केवल आर्थिक प्रबंधन नहीं था, बल्कि वैश्विक दबावों के बीच भारत की सामरिक स्वायत्तता और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन था। देखा जाये तो मौजूदा संकेत साफ बता रहे हैं कि नई दिल्ली लगातार कुशल रणनीति के साथ फैसले कर रही है। यही आक्रामक यथार्थवाद आज के दौर की मांग है।

बजट में वित्त मंत्री की चुनौती

बजट हमेशा ही भारत के आर्थिक और राजनीतिक कैलेंडर का महत्वपूर्ण क्षण होता है। बजट केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया के पीछे की गहराई में देश के विकास की जड़ें होती हैं। बजट से करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों और वेतनभोगियों से लेकर उद्योगपतियों और वाणिज्यिक घरानों तक को बहुत उम्मीदें होती हैं। बजट से पहले आम आदमी को उम्मीद होती है कि उन्हें टैक्स के बोझ से राहत मिलेगी या नहीं। क्या उनकी जेब में कुछ पैसा बचेगा या नहीं। इस वर्ष का बजट न केवल वित्तमंत्री के लिए बल्कि सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण समझा जा रहा है। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब भू-राजनीतिक और व्यापार वार्ता को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ से ग्लोबल ऑर्डर में डिसआर्डर दिखाई दे रहा है। इस बजट में वित्त मंत्री की चुनौती अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने और हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की होगी। निर्मला सीतारमण के सामने चुनौती घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक ज्यादा है। बजट में बिग-बेंग घोषणा की उम्मीदें कुछ ज्यादा नहीं हैं लेकिन सरकार का फोकस सर्टक्रल रिफार्म्स और वित्तीय विवेकशीलता पर रहेगा। पिछले वर्ष बहुत कुछ सकारात्मक रहा। महंगाई कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर रही। आरबीआई ने ब्याज दरें घटाईं। 12 लाख तक की आय को कर मुक्त किया गया। जीएसटी 2.0 में राहत दी गई जिससे बाजार में मांग बढ़ी और मानसून सामान्य रहा। इस वर्ष जियो पॉलिटिकल टैंशन, ट्रम्प के टैरिफ वॉर से उत्पन्न जटिल स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत। स्टॉक मार्किट का रोज-रोज लहूलुहान होना नकारात्मक बातें हैं। नीतिगत चुनौती की बात करें तो वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। कर्ज-जीडीपी अनुपात को 2031 तक 50 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर सरकार की इनकम नहीं बढ़ेगी तो कर्ज बढ़ेगा। इसलिए वित्तीय सतर्कता बहुत जरूरी है। भारत इस समय आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दम पर सैंकड़ों अरब डॉलर की ग्रोथ हासिल करने की कोशिश में लगा है। देश के पास एआई प्रतिभाओं का भंडार तो है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। ग्रोथ हासिल करने के लिए सिर्फ प्रतिक्रियाएं ही काफी नहीं हैं, उसके लिए बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। एक धारणा यह भी है कि एआई मौजूदा नौकरीपेशा लोगों को बेरोजगार करेगा। इसलिए जरूरी है कि भारत की एआई रणनीति को शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कम्पनियों द्वारा एआई को अपनाने के साथ-साथ गहराई से जोड़ा जाए। प्रतिभाओं के भंडार को रोजगार देने के लिए और एआई क्षमताएं विकसित करने के लिए वित्तमंत्री बजट में प्रावधान कर सकती हैं। उद्योग जगत की मांग भी यही है कि एआई क्षमता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। उम्मीद है कि आम बजट में सरकार स्टार्टअप्स की परिभाषा का दायरा बढ़ाए जिससे देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए मौके बन सकें। कई एआई स्टार्टअप कुछ वर्षों में अमेरिका और अन्य देशों में शिफ्ट हो चुके हैं।

क्योंकि वहां फ्रारकों, पैसों और एआई टेक्नोलॉजी तक आसान पहुंच है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों को बढ़ावा भी जरूरी है। देखना है कि वित्तमंत्री किस तरह से विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रबंधन करती हैं। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विनिर्माण और निर्यात पर स्पष्ट रूपरेखा तैयार करनी बहुत जरूरी है। हम एक खंडित विश्व और अस्थिर वैश्विक वातावरण में विनिर्माण और निर्यात को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस संबंध में क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है। इस बजट में मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों की नजरें स्टैंडर्ड डिडक्शन पर टिकी हुई हैं। महंगाई के बढ़ते बोझ को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए। इससे सैलरीड क्लास को सीधी राहत मिल सकेगी। हालांकि, नए आयकर कानून के चलते टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है लेकिन इस दौरान सबसे ऊंचे 30 प्रतिशत टैक्स स्लैब की लिमिट को 24 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए करने की मांग जरूर उठ रही है, ताकि ज्यादा सैलरी पाने वालों को भी राहत मिल सके। शेयर बाजार के निवेशकों और उद्यमियों के लिए भी यह बजट काफी अहम होगा। निवेशकों की मांग है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (एसटीसीजी) की दरों को आसान बनाया जाए। वहीं, छोटे उद्योग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सस्ता कर्ज उपलब्ध कराएगी और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खास इंसेंटिव देगी, ताकि अमेरिकी टैरिफ से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके और व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके। बजट से महिलाओं को भी बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों, छात्रों, व्यापारियों की भी अपनी उम्मीदें हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक काफी अच्छे हैं। बैंकिंग क्षेत्र काफी मजबूत है। खाद्यान्न से सरकारी गोदाम भरे पड़े हैं। ग्रामीण आय में उछाल आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तेज विकास और कम महंगाई के इस मेल को गोल्डी लोक्स बताया है लेकिन मजबूत दिखने वाले आंकड़ों के पीछे गहरी चुनौतियां भी होती हैं। ट्रम्प टैरिफ एक ऐसा गतिरोध है जिससे व्यापार पर पड़ने वाला प्रभाव साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नए बाजार हासिल करने के लिए एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिनमें हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता शामिल है। चिंता की बात यह है कि तेज विकास के बावजूद कार्पोरेट सैक्टर देश में निवेश नहीं कर रहा। कमजोर निजी निवेश इसलिए है कि कार्पोरेट सैक्टर का निवेश 2012 से ही ठप्प हुआ है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके लिए नियम सहज नहीं हैं।

सम्पादकीय...

हमारा समाज दिन-प्रतिदिन कहां जा रहा है

हैरान हूं मैं कि शादी के आयोजन हैं या दिखावा। शादी के नाम पर पैसे का दिखावा करते हुए 8-10 समारोह, परन्तु अपने शास्त्रों द्वारा निर्धारित किए गए कोई भी रीति-रिवाज उनमें नजर नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ हो-हल्ला और हुड़दंग ही होता है। हल्दी की रस्म में कोल्ड ड्रिंक और बीयर या वाइन के साथ होने वाले दूल्हा-दुल्हन को भिगोना, फिर वही बोतलें पकड़ कर भावी दूल्हा-दुल्हन फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। रस्मों के नाम पर ये जो रस्मों के मायने बदल गए हैं और तरीके अपने ही अंदाज में हो गए हैं, किसी शरीफ और संस्कारी इन्सान के गले से तो ये चीजें नहीं उतरतीं। आज कल की पीढ़ी के लिए तो शादी के मायने ही बदल गए हैं। जिन चीजों को हमारे बुजुर्ग सोच भी नहीं सकते थे, वे सब आजकल की पीढ़ी बड़े चाव से करती है- रस्मों-रिवाजों की धज्जियां शराब और हुक्के के छल्लों में उड़ाती दिखाई दे रही है और दूल्हा-दुल्हन भी इन सब से कोई परहेज नहीं करते। शादी वाले दिन की तो बात ही न करें। जब असली रस्म (फेरों) की बारी आती है तो पंडित जी को पैसे दे कर जल्दी से खत्म करने की बात पक्की कर ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ सजावट (तौबा-तौबा), कोई आम इन्सान तो सोच ही नहीं सकता जितना पैसा पानी की तरह इन सब पर बहाया जाता है। खाने-पीने में 50-50 तरह के स्नैक्स और मेन कोर्स में भी इतनी डिशेज कि आप खा ही नहीं सकते। और चलिए बाद में जरा इस्तेमाल की गई प्लेटें देखें, जो खाली मिलेंगी ही नहीं। इतना खाना डाल कर फिर फैंकना, यही तो हमारी शान है और जरा सोचिए उस गरीब रिक्शा वाले या सब्जी वाले अथवा मोची या घर में रखी नौकरानी के परिवार बारे, जो हमारी बची हुई सब्जी को माथे से लगाकर अपने घर जाकर खुशी से खाते हैं। उन के लिए वही पार्टी है। जितना पैसा आजकल शादियों में लग रहा है, उससे किसी गरीब का घर बन और बस सकता है, किसी गरीब की लड़कियों की शादियां हो सकती हैं। कोई गरीब मरने से बच सकता है। हमारा समाज दिन-प्रतिदिन कहां जा रहा है, जहां न बड़ों की इज्जत है, न अपनों से प्यार। भाई-भाई का दुश्मन है। खून सफेद हो चुके हैं, किसी भी रिश्ते का कोई सम्मान तो रहा ही नहीं। शादी-ब्याह पर इतना पैसा लगाकर दिखावा करने वाले किसी गरीब की लड़की को पढ़ा-लिखा दें, उसकी शादी करवा दें। किसी गरीब के घर में राशन का महीना बांध लें तो हमारे देश की गरीबी कम होगी। यह तो हाथ से हाथ की बात है, सोच की बात है। लिखने को तो बहुत कुछ है परन्तु अभी सिर्फ इतना ही, जो महसूस किया, जो चाहा, वही लिखा। शादियों का मौसम है, जाकर बार-बार दिखावा देख कर, प्लेटों में जूठन देख कर गरीब बच्चों या उनकी माताओं को उस जूठन में से चुग-चुग कर खाता देख कर लिखने को दिल कर आया।

थरूर- राहुल, मन का यह गुब्बार

पिछले काफी अरसे से एक-दूसरे से खफा-खफा चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी ही पार्टी के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर की एक विलंबित बैठक पिछले दिनों दिल्ली में संपन्न हुई। बंद कमरे में कोई दो घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो मौजूद रहे, पर थरूर की भावनाओं को शिरोधार्य करते राहुल ने अपने सबसे भरोसेमंद केसी वेणुगोपाल को इस मीटिंग से बाहर रखा, क्योंकि थरूर के राजी होने की पहली शर्त ही यही थी।

वैसे पिछले कोई एक साल से राहुल थरूर को बेतरह 'इग्नोर' कर रहे थे, थरूर ने लगभग 7-8 मैसेज राहुल को भेजे, पर राहुल की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया। इस पिछले एक साल में थरूर ने राहुल के ऑफिस से कितने ही दफे मिलने का समय मांगा, पर नेता प्रतिपक्ष के साथ उनकी मुलाकात का यह वक्त कभी मुकर्रर ही नहीं हुआ। ये वेणुगोपाल ही थे जिन्होंने राहुल को थरूर से मिलने के लिए राजी करवाया, बकौल वेणुगोपाल केरल की कोई चार लोकसभा सीटों पर थरूर का असर है, वहां इनके लोग भी हैं, सो 'डैमेज कंट्रोल' के लिए उन्हें मना लेना ही ठीक रहेगा।

सो, जैसे ही राहुल संग थरूर की यह मुलाकात शुरू हुई, थरूर ने छूटते ही राहुल से कह दिया- 'मैंने आपको कोई सात-आठ बार मैसेज भेजे, पर आपने उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा?' राहुल ने स्वीकार किया- 'हां, मैं आपसे बहुत नाराज था, इसीलिए जवाब देने की जरूरत नहीं समझी।' थरूर ने हंस कर कहा- 'नाराज थे तो मैसेज में नाराजगी व्यक्त कर देते, मैं समझ जाता, वैसे भी नेता वही है जो संवाद छोड़ता नहीं, उसे बुनता है।' फिर थरूर ने बेखटके राहुल के समक्ष अपने विचार रखने शुरू कर दिए, 'आप बुरा मत मानिए, पर सच तो यही है कि आज न कांग्रेस के पास कोई प्लॉन है, न कोई दिशा और न ही रफ्तार, इसका मैं एकमात्र कारण समझ पा रहा हूं कि आपको गैर राजनीतिक लोगों ने घेर रखा है और आप सिर्फ उन्हीं की सलाहों पर चलते हैं।' खड़गे ने मामले की नजाकत को भांपते बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ा और कहा- 'हम यहां केरल पर बात करने के लिए जमा हुए हैं, बातचीत का फोकस वही रहे।' तो इस पर थरूर ने कहा-'इस बार केरल में लेफ्ट सरकार के खिलाफ जो माहौल है उसमें कांग्रेस बिना कुछ ज्यादा किए भी चुनाव जीत सकती है। भाजपा लड़ तो रही है महज एक-चौथाई सीट, सो उसका वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा, पर सीटें गिनती की 4-5 आएंगी। सो आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं केरल के अलावा असम, बंगाल, तमिलनाडु हर राज्य में जाने को तैयार हूं, आप पहले मुझे कोई जिम्मेदारी देकर तो देखिए। आप संगठन में लेकर मुझे किसी राज्य का प्रभार भी दे सकते थे।' फिर थरूर ने मन का यह गुब्बार भी निकाला कि 'इस बार भी पार्टी उन्हें सदन में राहुल के बाद डिप्टी लीडर बना सकती थी, पर इसके लिए चुना गया गौरव गोगोई को।' फिर थरूर ने राहुल को चेताया कि 'वे बार-बार हर महीने विदेश चले जाते हैं इसका भी लोगों पर सकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है। रोज-बरोज कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है, पर इस बारे में पार्टी कुछ कर नहीं रही।' राहुल ने कहा- '2029 का चुनाव मोदी का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद भाजपा ढलान पर आएगी।' थरूर ने कहा- 'अब भी आप भाजपा की योजनाओं को बहुत कम करके आंक रहे हैं, 2027 के बाद एक बड़ा परिसीमन होगा, हिंदी भाषी राज्यों में जहां भाजपा मजबूत है वहां की लोकसभा सीटों में इजाफा होगा और आबादी के अनुपात के अनुसार साउथ की सीटें कम होंगी, यह एक बहुत बड़ा गेम प्लॉन है, इसी को ध्यान में रख कर मोदी ने नया संसद भवन बनवाया है, जिसकी क्षमता साढ़े सात सौ सांसदों की है।' फिर तय हुआ कि राहुल थरूर के संग एक बार फिर से बैठेंगे ताकि उनकी सलाहों पर ठीक से कान धरा जा सके।

हर द्वार क्यों खटखटा रहे हैं पीके

बिहार चुनाव में बुरी तरह मुंह की खाने के बाद प्रशांत किशोर अपने एक नए राजनीतिक प्रादुर्भाव के लिए बेकरार हैं। बिहार में उनकी नवसर्जित जन सुराज पार्टी दरकने की कगार पर है और पीके सियासी बियाबां की खाक छानने में जुटे हैं।

पिछले दिनों इनकी कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी से एक लंबी और सारगर्भित मुलाकात हुई थी। सूत्रों की मानें तो प्रियंका संग हुई अपनी इस मुलाकात में पीके ने साफ कर दिया था कि 'वे अपनी जन सुराज पार्टी का विलय कांग्रेस में करने को तैयार हैं, पर उनकी शर्त बस इतनी है कि बदले में उन्हें बिहार प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए, ताकि वे पूरे बिहार में घूम-घूम कर ग्राम रूट पर कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने का काम कर सकें।' सनद रहे कि इससे पहले पटना में पीके ने अपनी पार्टी की 16 सदस्यीय कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिनमें से 12 कोर कमेटी मेंबर पीके की इस राय से इत्तफाक रखते थे कि 'अगर जन सुराज को बचाए रखना है तो अतिशीघ्र पीके को किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना होगा।' समझा जाता है कि इसके बाद प्रियंका ने पीके के कांग्रेस में आने की और अपनी पार्टी के विलय के संदर्भ में राहुल गांधी से बात की। सूत्र बताते हैं कि राहुल ने छूटते ही बहन से कहा- 'यह बेकार का आईडिया है, इस पर माथा-पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन पर पीके के पास कोई वोट नहीं, वह सिर्फ मीडिया के सहारे राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, बातें बड़ी-बड़ी हैं, पर डिलीवरी नहीं है, वह अगर कांग्रेस में आ भी गए तो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं।'

इसके बाद पीके का दो-तीन दफे प्रियंका को फोन आया तो प्रियंका ने उनसे टालू अंदाज में कहा- 'राहुल अभी बहुत व्यस्त चल रहे हैं, इस बारे में उनसे बात करने का हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा है।' चतुर सुजान पीके समझ गए कि राहुल उनको लेकर इतने पॉजिटिव नहीं हैं तो फिर उन्होंने उदयकांत मिश्रा के मार्फत जदयू में जाने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए, पर यहां उनके आड़े ललन सिंह आ रहे हैं, ललन कह रहे हैं

'ये तो वही पीके हैं जो जदयू के 25 सीटों पर सिमटने की भविष्यवाणी कर रहे थे।' वहीं पीके की पार्टी के ही एक अन्य नेता आरसीपी सिंह की भी जदयू में घर वापसी के चर्चे जोरों पर हैं, सनद रहे कि इस दफे के बिहार विधानसभा चुनाव में आरसीपी की पुत्री लता सिंह ने जन सुराज के टिकट पर नालंदा के अस्थावां सीट से चुनाव लड़ा था, पर वहां उन्हें बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ा था हालांकि ललन आरसीपी की घर वापसी के भी विरोध में हैं, उनका कहना है कि 'ये वही आरसीपी हैं जो पार्टी अध्यक्ष रहते जदयू को 72 से 42 सीटों पर ले आए थे।' पर समझा जाता है कि स्वयं नीतीश आरसीपी की घर वापसी को लेकर किंचित उत्साही हैं, सो यहां उनका मामला बन सकता है।

नितिन नवीन की मेजबानी

भाजपा के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सियासी सुर्खियों की सवारी गांठने में सिद्धहस्त होना चाहते हैं, जब से वे लुटियंस के अपने नए बंगले 9 सुनहरी बाग लेन में शिफ्ट हुए हैं, उनसे मिलने वालों की बाढ़ आई हुई है। पिछले दिनों अध्यक्ष जी ने कोई 12-15 सीनियर पत्रकारों को खाने के लिए अपने घर बुला लिया, इसमें से ज्यादातर भाजपा बीट कवर करने वाले पत्रकार थे और इनमें से भी अधिकांश बिहार से ताल्लुक रखने वाले थे। पत्रकारों से अपनी अनौपचारिक बातचीत में अध्यक्ष महोदय बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे, उनकी मेहमाननवाजी शानदार थी और उनका रुख बेहद दोस्ताना था।

और अंत में

कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब कोलकाता से वापस लौट कर अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस नेतृत्व को संकेत दे दिए हैं कि 'वे 2027 के चुनाव में कांग्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 सीटें छोड़ सकते हैं।' अखिलेश को इस बात का बखूबी इल्म है कि राहुल-प्रियंका इस प्रस्ताव पर कतई सहमत नहीं होंगे, सो उनके लिए 'एकला चलो' का राग बुलंद करना आसान हो जाएगा। दरअसल, अखिलेश की असली चिंता कांग्रेस के 'स्ट्राइक रेट' को लेकर है बिहार में कांग्रेस ने तेजस्वी से लड़-झगड़ कर 65 सीटें हासिल कर लीं, पर जीते कांग्रेस के सिर्फ 6 लोग, यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10 फीसदी से भी कम रहा। स्वयं राहुल गांधी ने बिहार में 11 जनसभाओं को संबोधित किया। सो, अखिलेश खम्म ठोक कर कोलकाता में दीदी की लीडरशिप पर मुहर लगा यह कह कर आए हैं कि 'अगर भाजपा से कोई एक नेता लोहा ले सकता है तो वह है ममता दीदी। तो मोदी विरोध की देशभर में अलख जगाने वाले राहुल गांधी कहां गए?' कांग्रेस को तमिलनाडु में भी इसी तरह की परेशानियों से दो-चार होना पड़ रहा है, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन 12 पार्टियों के गठबंधन (इनमें से एक कांग्रेस भी है) के साथ चुनाव में जा रहे हैं, पर कहते हैं चुनाव जीते तो सत्ता में हिस्सेदारी सिर्फ डीएमके की ही रहेगी, इसी बात लेकर राहुल गांधी डीएमके संसदीय दल की नेता कानिमोझी से बुधवार को मिले और कहा कि 'कांग्रेस के लिए सीटें भले 25 छोड़ दी जाए, पर सरकार बनने पर उसमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए।'

जी राम जी आजीविकाओं की दिशा में भारत की यात्रा

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 इस क्रमिक विकास को प्रतिबिंबित करता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में सुधार के माध्यम से यह अधिनियम इस तथ्य को मान्यता देता है कि सतत् ग्रामीण समृद्धि केवल रोजगार सृजन पर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलेपन तथा आजीविकाओं के संरक्षण पर भी आधारित होनी चाहिए। यह समेकित दृष्टिकोण ऐसे समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जब ग्रामीण समुदाय जलवायु परिवर्तनशीलता, चरम मौसमीय घटनाओं और संसाधन दबाव के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता का सामना कर रहे हैं। जी राम जी अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मजदूरी आधारित रोजगार को चार प्राथमिक क्षेत्रों के साथ संरेखित करने पर विशेष बल दिया गया है–जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित अवसंरचना तथा चरम मौसमीय घटनाओं के शमन से जुड़े कार्य। यह ग्रामीण रोजगार नीति के पर्यावरणीय और लचीलापन संबंधी आयामों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जल से संबंधित कार्य, मृदा एवं भूमि संरक्षण, जल निकासी प्रणालियां तथा जलवायु-अनुकूल अवसंरचना कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ बाढ़, सूखा और भूमि क्षरण के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ऐसी परिसंपत्तियां प्रभावी ढंग से नियोजित तथा कार्यान्वित की जाती हैं तो वे कई लाभ उत्पन्न करती हैं–अल्पकालिक रोजगार सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन तथा दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा। इन क्षेत्रों पर अधिनियम का विशेष बल इस तथ्य को रेखांकित करता है कि रोजगार कार्यक्रम एक साथ सामाजिक संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सकते हैं। अधिनियम की नियोजन पारिस्थितिकी–जिसका केंद्र विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं हैं तथा जिसमें परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अंतर्गत एकीकृत किया गया है–ग्रामीण विकास के लिए एक सुसंगत और भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करती है। विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से पंचायतों को स्थानीय प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर मिलता है, जबकि राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण व्यापक अवसंरचना एवं विकास उद्देश्यों के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है। कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से यह ढांचा रोजगार गारंटी के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, स्थायित्व और प्रासंगिकता में सुधार का अवसर प्रदान करता है। पर्याप्त तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से पंचायती राज संस्थान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि सार्वजनिक कार्य, संसाधन संरक्षण तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सार्थक योगदान दें। अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित पारदर्शिता तंत्र, डिजिटल निगरानी उपकरण और सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही को और सुदृढ़ करते हैं तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं। सतत् विकास के प्रति वचनबद्ध एक शोध संस्थान के रूप में, टेरी ने यह समझने के लिए व्यापक रूप से कार्य किया है कि ग्रामीण समुदायों में लचीलापन विकसित करने के लिए सामाजिक संरक्षण तंत्रों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है। हमारे शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि जब रोजगार कार्यक्रमों को पर्यावरणीय योजना और जोखिम-सूचित रूपरेखा के साथ जोड़ा जाता है तो वे घरेलू तथा सामुदायिक–दोनों स्तरों पर अनुकूलन क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। टेरी ने जलवायु लचीलापन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन तथा आजीविका की निरन्तरता को सम्मिलित करने हेतु नीतिगत ढांचों के पुनरोद्धार और सुदृढ़ीकरण से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं में विश्लेषणात्मक योगदान प्रदान किया है। इसमें कार्यक्रम अभिकल्पना में लचीलापन संबंधी पहलुओं के एकीकरण को समर्थन देना तथा रोजगार सृजन के साथ-साथ दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को प्रतिबिंबित करने वाले संकेतकों की पहचान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, टेरी ने ऐसे वित्तीय मॉडल और नियोजन दृष्टिकोणों का अध्ययन किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को अधिकतम करने में मदद कर सकते हैं–सामुदायिक परिसंपत्तियों को सुदृढ़ करना, दीर्घकालिक संवेदनशीलता को कम करना, और संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ाना। इस प्रकार के शोध-आधारित योगदान का उद्देश्य सरकारी पहलों का पूरक होना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करना होता है।

आजीविकाओं का संरक्षण

जी राम जी अधिनियम का दृष्टिकोण ग्रामीण आजीविकाओं को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को प्रमुखता देता है। जल सुरक्षा, कनेक्टिविटी, भंडारण और जलवायु-सहनशील अवसंरचना में निवेश प्रत्यक्ष रूप से कृषि, सहायक गतिविधियों और गैर-कृषि आजीविकाओं का समर्थन करता है। साथ ही, अधिनियम में शामिल प्रावधान, जैसे कि प्रमुख कृषि सीजन के दौरान सार्वजनिक कार्यों में राज्य-निर्धारित विराम, यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि रोजगार सृजन कृषि गतिविधियों के पूरक के रूप में बना रहे। एक कानूनी रोजगार गारंटी की निरंतरता, साथ ही जहाँ कार्य प्रदान नहीं किया जाता वहां बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान, अधिनियम के सामाजिक संरक्षण उद्देश्यों को और मजबूत करते हैं। पूर्वानुमेय नियोजन और विश्लेषण के साथ, प्रशासनिक क्षमता के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से, कार्यक्रम की प्रभावशीलता और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है।

'विकसित भारत 2047' की ओर

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम समावेशी विकास प्रदान करने में एक बड़ी रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। उनकी सफलता का मूल्यांकन केवल सृजित कार्यदिवसों की संख्या से नहीं, बल्कि लचीली आजीविकाओं, स्थायी अवसंरचना और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उनके योगदान से किया जाएगा। इस संदर्भ में, विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा प्रस्तुत करता है। पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को सम्मिलित करके, जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाकर और विकेन्द्रीकृत नियोजन को मजबूत करके यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को सतत् विकास की आधारशिला के रूप में स्थापित करता है। सरकार, शोध संस्थानों, राज्यों और स्थानीय समुदायों के बीच निरंतर सहयोग के माध्यम से यह सुधार यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि ग्रामीण रोजगार वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य हेतु लचीलेपन में भी सार्थक योगदान दे–आज आजीविकाओं का समर्थन करते हुए कल की समृद्धि

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पॅचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/0882)

भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे संत रविदास, सपाईयो ने किया नमन

मुरादाबाद।

समाजवादी पार्टी महानगर इकाई के कैंप कार्यालय मकबरा फाटक पर संत शिरोमणि रविदास एवं संत नरहरी दास (सोनार) की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दोनों संतों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार किया गया। वक्ताओं ने संत रविदास एवं संत नरहरी दास के जीवन, उनकी सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे और मानवता के संदेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज को एकता, सद्भाव और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्री इकबाल हुसैन अंसारी ने की तथा संचालन डॉ. सोमवीर यादव ने किया। इस अवसर पर राशिद

हुसैन अंसारी (महानगर अध्यक्ष, मज़दूर सभा), सलीम वारसी, लालू परवेज़, शमशाद हुसैन अंसारी, शननू भाई साहब, मोहम्मद उमेर, शाहिद अली, मोहम्मद कामिल, मोहम्मद वासिफ, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद वसीम, असद खान, बिलाल मालिक, अरबाज़ फैसल, मोहम्मद शमशाद, मसरूर हसन, मोहम्मद शरीफ, फरमान खान, जुनेद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा कि संत रविदास और संत नरहरी दास ने समाज को समानता, प्रेम और मानवता का जो संदेश दिया, वह आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय, भाईचारे और कमजोर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का कार्य करती रहेगी। श्री अंसारी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संतों की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लें। इसी अवसर पर संगठन को सशक्त करने के उद्देश्य से महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी द्वारा वार्ड संख्या 45 के अध्यक्ष पद पर मोहम्मद उमेर की नियुक्ति की घोषणा की गई। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं दीं। अंत में सभी ने संतों के आदर्शों पर चलने तथा समाज में प्रेम, भाईचारे और सामाजिक न्याय को मजबूत करने का संकल्प लिया।

गंगा मैया की महाआरती कर लिया प्रदूषण मुक्ति का लिया संकल्प

मुरादाबाद। राष्ट्रीय पुजारी परिषद द्वारा माघ पूर्णिमा एवं सन्त रविदास जयंती के अवसर पर श्री परशुराम गंगा मैय्या की भव्य महाआरती एवं सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं सन्त रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके दिखाई मार्ग पर चलने के साथ प्रदूषण मुक्ति का संकल्प,प्राचीन शिव राम गंगा मन्दिर घाट अटल घाट निकट कटघर रेलवे स्टेशन मुरादाबाद पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पुजारी परिषद के संस्थापक श्याम कृष्ण रस्तौगी ने कहा कि मां गंगा और उसकी सहायक नदियों के के प्रति हिंदू समाज की गहरी आस्था और श्रद्धा है परंतु सरकार और समाज के कुछ लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है पर सफाई कहां हो रही है दिखाई नहीं देता सभी नदियों में सैकड़ो गंदे नाले मिल रहे हैं सरकार में बैठे अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहे । नदियों में रात दिन अवैध खनन हो रहा है और मुरादाबाद में बह रही श्री परशुराम गंगा में तो ऐसा लगता है कि वह केवल भैंसों के लिए ही रह रही है सुबह से लेकर शाम तक भैंसें ही भैंसें दिखाई देती है। राष्ट्रीय पुजारी परिषद मांग करता है कि रामगंगा में जानवरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो गन्दे नाले मिल रहे हैं उन्हें तुरंत बंद किया जाए ।

राजस्व ग्राम सेमरहना का डीएम ने किया भ्रमण

बहराइच। जिले की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) अन्तर्गत राजस्व ग्राम भरथापुर के हितग्राहियों को ग्राम सभा सेमरहना में विस्थापित किये जाने की कार्यवाही का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद, उप जिलाधिकारी मोतीपु मिहींपुरवा (मोतीपुर) राम दयाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रद्युम्न सिंह, अधि.अभि. लो.नि.वि. निर्माण खण्ड-1 अमर सिंह, तहसीलदार धर्मेन्द्र कुमार, अधि.अधि. नगर पंचायत जंग बहादुर, खण्ड विकास अधिकारी मिहींपुरवा व अन्य अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी राम दयाल से भूमि पैमाईश के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। डीएम ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए कृषि आवंटन हेतु भी भूमि का चिन्हांकन कर लिया जाय।

नेपाल सीमा के मरीजों को जागरूक व परीक्षण कर होगा इलाज- डॉ सारिका

बहराइच।

नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 का शुभारंभ बहराइच जनपद में 6 फरवरी से होगा। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से जनपद के 38 सीमावर्ती गांव में 6 एवं 7 फरवरी को चिकित्सा शिविर लगाकर मरीज का परीक्षण किया जाएगा तथा 8 फरवरी को किसान डिग्री कॉलेज परिसर में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा यह जानकारी नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन की जिला अध्यक्ष डॉ सारिका साहू ने दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में केजीएमयू आरएमएल एसजीपीजीआई महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सक चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले प्रहरी हो या वहां निवास करने वाले वनवासी बंधु उनका स्वास्थ्य ही राष्ट्र की शक्ति है इसी संकल्प के साथ नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन और श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास विगत 5 वर्षों

से दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा की अलख जगह रहे हैं। इस वर्ष की सेवा यात्रा अपने छठे सोपान पर है यह यात्रा बहराइच जनपद के बनवासी क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा और सेवा के समर्पण को जोड़कर एक नया इतिहास रचने जा रही है। उन्होंने बताया कि महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं शिक्षक एवं छात्रों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा यात्रा के संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मिहींपुरवा विकासखंड के 22 सीमावर्ती गांव विष्नापुर अंबा, फकीरपुरी, वर्दियां, सलारपुर मूर्तियां, भगड़िया, गोपिया, जोगनिया, करमोहना, कांजीबाग, अयोध्या गांव, हरखापुर, रामपुरवा, सुजौली चहलवा चितलहवा, गौरापिपरा, सोगवा, पड़रिया, मटेरीकला, सोहनी बलाई गांव, मदारिया, धरमापुर में 6 व 7 फरवरी को चिकित्सा शिविर का आयोजन होगा। इसी क्रम में विकासखंड बाबागंज के बाबागंज में 6 फरवरी को मिहीपुरवा, गोकुलपुरवा, रामबख्शपूरवा, भगवानपुर करिंगा, जैतापुर,खैरनिया, रामपुर गंगापुर एवं 7 फरवरी को जमदान, सिरसिया, राजा गांव ,रामनगर गुलरिया, सामलगांव,

20 हजार से अधिक मरीजों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण- धर्मेंद्र

बेलवरिया, माधवपुर रघुनाथ, झटहा मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इस बार 20000 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का लक्ष्य लिया गया है।

दिनांक 8 फरवरी को किसान डिग्री कॉलेज परिसर में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य यात्रा के तहत 20 हजार से अधिक मरीजों को देखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रेस वार्ता में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के मेजर डॉ एसपी सिंह ,डॉ विकास मिश्रा, डॉ बृजेश शुक्ला, डॉ दिव्येश बरनवाल, डॉ मनीष शुक्ला, डॉ रामेंद्र त्रिपाठी ,डॉ अमिताभ मिश्रा डॉ दिवाकर दत्त त्रिपाठी, डॉ उपेंद्र वर्मा, डॉ रामकुमार विभाग प्रचार प्रमुख अतुल गौड़, जिला प्रचार प्रमुख विपिन आदि उपस्थित रहे।

माघी पूर्णिमा का पावन पर्व : आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण

माघ मेले में एक महीने तक या पता पर पूजा पाठ करने वाले कल्पवासियों का आज आखिरी स्नान पर्व पोस्ट पूर्णिमा

प्रशासन के अनुसार माघ मेले में अब तक लगभग 19 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था व पुण्य की डुबकी लगाई

प्रयागराज।

भारतीय सनातन परम्परा में माघ मास को पुण्य, तप, दान एवं आत्मशुद्धि का विशेष काल माना गया है। इसी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से स्नान, दान, जप, तप तथा धर्मशास्त्रीय अनुष्ठानों के लिए श्रेष्ठ माना गया है।ज्योतिषाचार्य द्वारा प्रदत्त प्रामाणिक ज्योतिषीय एवं धर्मशास्त्रीय गणनाओं के अनुसार वर्ष 2026 में माघी पूर्णिमा का पुण्यकाल अत्यन्त विशिष्ट एवं दुर्लभ संयोगों से युक्त है।

शास्त्रीय महत्त्व

धर्मशास्त्रों में कहा गया है–यां तिथिं समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः सा तिथिः सकला ज्ञेया स्नानदानजपादिषु। अर्थात् जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है, वही तिथि स्नान, दान एवं जप आदि के लिए पूर्ण रूप से मान्य होती है। माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, विशेषतः गंगा-स्नान, ब्राह्मण-भोजन, वस्त्र, अन्न, तिल, घृत एवं स्वर्ण दान, साथ ही विष्णु, शिव एवं सूर्योपासना का विशेष विधान है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान एवं जप अक्षय फल प्रदान करता है।

ज्योतिषीय विशेषता (2026)

*ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार वर्ष 2026 में 01 फरवरी 2026 (रविवार) को प्रातः 05:53 बजे माघी पूर्णिमा तिथि का आरम्भ हो रहा है

तथा 02 फरवरी 2026 (सोमवार) को प्रातः 03:39 बजे इसका समापन होगा। इस प्रकार कुल 21 घंटे 46 मिनट की पूर्णिमा तिथि उपलब्ध रहेगी। इस वर्ष सूर्य मकर राशि में तथा चन्द्रमा अपनी स्वराशि कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिससे विशेष पुण्यप्रद योग का निर्माण हो रहा है। इसके कारण स्नान, दान एवं आध्यात्मिक साधना के लिए दीर्घ एवं श्रेष्ठ काल प्राप्त हो रहा है। विशेष रूप से 01 फरवरी 2026 को प्रातः 05:53 से 10:59 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र एवं प्रीति योग के कारण सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है*। इसके अतिरिक्त रात्रि के पश्चात 02 फरवरी 2026 को सूर्योदय तक भी माघी पूर्णिमा के निमित्त धार्मिक कृत्य सम्पन्न किए जा सकते हैं।

***सामाजिक एवं सांस्कृतिक सन्देश**

माघी पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, दानशीलता एवं लोककल्याण का भी संदेश देती है।

इस अवसर पर किया गया दान समाज के दुर्बल वर्गों के लिए सहारा बनता है तथा व्यक्ति के भीतर करुणा, संयम एवं आध्यात्मिक चेतना का विकास करता है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन ने मनाया चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की पुण्यतिथि

बहराइच।

पूरे देश में प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को सुबह दस बजे दस मिनट अपने पूर्वजों स्वतंत्रता सेनानियों,वीर योद्धाओं और शहीदों को श्रद्धांजलि,पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।उसी क्रम में आज स्थानीय सेनानी भवन सभागार में अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की पुण्यतिथि मनाई गई। उपस्थित सेनानी उत्तराधिकारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन राज्य इकाई उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक महामंत्री रमेश कुमार मिश्र ने बताया कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का जन्म 26 नवंबर 1914 को अविभाजित पंजाब (अब हरियाणा) के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव के एक जेलदार परिवार में हुआ था। रणबीर सिंह हुड्डा की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल और बाद में गोहाना (सोनीपत) के गुरुकुल बिन्सवाल कलां में प्राप्त की, जो आर्य समाज कार्यकर्ता और समाज सुधारक, भगत फूलसिंह द्वारा संचालित था। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद रणबीर सिंह हुड्डा ने रोहतक के वैश हाईस्कूल में दाखिला लिया,

उन्होंने 1933 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और उच्च अध्ययन के लिए रोहतक के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, उन्होंने 1935 में अपनी एफ ए की परीक्षा पास की।बाद में वह दिल्ली के रामजस कालेज से 1937 में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। उन्हें 2007 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जिला इकाई बहराइच एवं श्रावस्ती संगठन के संरक्षक एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने कहा कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा 1930 के दशक में भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए गांधी वादी सेना में शामिल हुए, उन्हें पहली बार 1941 में एक सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल की सलाखों के पीछे रखा गया था।इस संगठन के जिला महामंत्री राजू मिश्र उर्फ मुन्ना भैया ने कहा कि एक नवंबर 1966को एक नये राज्य के रूप में हरियाणा के गठन के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक आधार हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने 1968में उपचुनाव में विधानसभा सीट जीती।वह 1972 में राज्य सभा के लिए चुने गए और स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन की शुरुआत के लिए काम किया।1976-77 में राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता बने, रणबीर सिंह हुड्डा भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के संस्थापक महासचिव थे। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा अपने गोलोकवासी होने एक फरवरी 2009 तक अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे।अन्त में उपस्थित सभी सेनानी उत्तराधिकारियों ने उनके मातृभूमि को गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने हेतु नमन करते हुए कार्यक्रम समाप्त किया। कार्यक्रम में निकुंज मिश्र एडवोकेट,तुलसी राम मौर्य, रवीन्द्र कुमार सिंह, शिव नारायण, राकेश त्रिवेदी, परमजीत, दोस्त मोहम्मद सहित तमाम सेनानी उत्तराधिकारी मौजूद रहे।

ट्रैफिक पुलिस को ब्लैकमेल कर उगाही करने वाले सिंडिकेट के दो और सदस्य गिरफ्तार, अब तक 10 शातिर सलाखों के पीछे

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल के जरिए उगाही करने वाले एक कुख्यात सिंडिकेट के दो और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आमिर चौधरी उर्फ सिकंदर और संजय गुप्ता हैं। दोनों पहले से गिरफ्तार सरगनाओं जीशान अली और राजकुमार उर्फ राजू मीना के सक्रिय सहयोगी थे। अब तक इस सिंडिकेट के कुल 10 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के अनुसार, यह सिंडिकेट दो अलग-अलग गिरोहों के रूप में सक्रिय था। एक गिरोह जीशान अली के नेतृत्व में और दूसरा राजकुमार मीना के नेतृत्व में काम करता था। दोनों गिरोह ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चालान काटने या कागजात जांच के दौरान गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्ड करते थे, बाद में उन वीडियो में हेरफेर कर विभागीय जांच, निलंबन, विजिलेंस कार्रवाई या झूठे आपराधिक मामलों की धमकी देकर बड़ी रकम वसूलते थे। मामला 29 अप्रैल को दर्ज हुआ था, जब एक व्यावसायिक वाहन चालक ने नकली 3 मार्च स्टिकर दिखाकर चालान से छूट लेने की कोशिश की। जांच में वाहन चालक के व्हाट्सएप ग्रुप की पड़ताल से इस संगठित अपराध सिंडिकेट का खुलासा हुआ। यह गिरोह व्यावसायिक वाहन चालकों-मालिकों को भी धोखा देता था और ट्रैफिक पुलिस से उगाही का मुख्य धंधा चलाता था। जीशान अली को मुख्य मास्टरमाइंड माना गया है। आमिर चौधरी (जौहरीपुर, करावल नगर निवासी, पेशे से कैब ड्राइवर) जीशान अली का मुख्य साथी था। उसे एक सरकारी अधिकारी से उगाही करते पकड़ा गया। उसके पास से 60 हजार रुपये नकद और दो मोबाइल बरामद हुए। यह जीशान अली वाले मामले में सातवीं गिरफ्तारी है। संजय गुप्ता (पेशे से ट्रांसपोर्टर) राजकुमार मीना का प्रमुख सहयोगी था। राजकुमार और शिवजुद्दीन ने उसे वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग की ट्रेनिंग दी थी। वह सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल कर जबरन वसूली करता था। यह राजकुमार वाले मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। उसके खिलाफ पहले से ज्योति नगर (2022 में उगाही), बुराड़ी (2009 में ठगी) और कमला मार्केट (2015 में POCSO एक्ट) के मामले दर्ज हैं। दोनों गिरफ्तारियां 17 और 20 जनवरी को एसीपी संजय कुमार नागपाल तथा इंस्पेक्टर अरुण सिंधु और केके शर्मा की टीम ने अलग-अलग ऑपरेशनों में कीं। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल के जरिए उगाही करने वाले एक कुख्यात सिंडिकेट के दो और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आमिर चौधरी उर्फ सिकंदर और संजय गुप्ता हैं। दोनों पहले से गिरफ्तार सरगनाओं जीशान अली और राजकुमार उर्फ राजू मीना के सक्रिय सहयोगी थे। अब तक इस सिंडिकेट के कुल 10 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के अनुसार, यह सिंडिकेट दो अलग-अलग गिरोहों के रूप में सक्रिय था। एक गिरोह जीशान अली के नेतृत्व में और दूसरा राजकुमार मीना के नेतृत्व में काम करता था। दोनों गिरोह ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चालान काटने या कागजात जांच के दौरान गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्ड करते थे, बाद में उन वीडियो में हेरफेर कर विभागीय जांच, निलंबन, विजिलेंस कार्रवाई या झूठे आपराधिक मामलों की धमकी देकर बड़ी रकम वसूलते थे। मामला 29 अप्रैल को दर्ज हुआ था, जब एक व्यावसायिक वाहन चालक ने नकली 3 मार्च स्टिकर दिखाकर चालान से छूट लेने की कोशिश की। जांच में वाहन चालक के व्हाट्सएप ग्रुप की पड़ताल से इस संगठित अपराध सिंडिकेट का खुलासा हुआ। यह गिरोह व्यावसायिक वाहन चालकों-मालिकों को भी धोखा देता था।

और ट्रैफिक पुलिस से उगाही का मुख्य धंधा चलाता था। जीशान अली को मुख्य मास्टरमाइंड माना गया है। आमिर चौधरी (जौहरीपुर, करावल नगर निवासी, पेशे से कैब ड्राइवर) जीशान अली का मुख्य साथी था। उसे एक सरकारी अधिकारी से उगाही करते पकड़ा गया।

देश को बजट से नई राह मिलेगी- मोदी

बजट 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बताया गेम चेंजर

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 को भारत के विकसित भारत 2047 के सफर की मजबूत नींव बताते हुए इसकी सराहना की और कहा कि यह देश में चल रही सुधार की रफ्तार को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने लगातार नौवां बजट पेश किया।

राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने को उड़ान के लिए एक मजबूत नींव है। यह बजट भारत में चल रही सुधार की रफ्तार को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा।

अभूतपूर्व सुधारों ने भारत के साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खुले आसमान के नीचे विकास के अवसर प्रदान किए हैं। हमारा प्रयास कौशल, व्यापकता और स्थिरता को निरंतर मजबूत करना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक सबसे बड़ी संपत्ति हैं और सरकार ने उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके नागरिक होते हैं। हाल के वर्षों में, हमारी सरकार ने अपने नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। राजकोषीय और आर्थिक रणनीति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा अनूठा बजट है जो राजकोषीय घाटे को कम करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने पर केंद्रित है और इसके साथ ही, इस बजट में उच्च पूंजीगत व्यय और उच्च विकास का संयोजन भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। भारत के 14 करोड़ नागरिक न केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट हैं, बल्कि हम जल्द से जल्द तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। यह देश के करोड़ों नागरिकों का संकल्प है। विश्व के एक विश्वसनीय, लोकतांत्रिक सहयोगी और एक विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में, भारत की भूमिका निरंतर विस्तारित हो रही है। भारत द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों - सर्वव्यापी समझौतों की जननी - का अधिकतम लाभ भारत के युवाओं और भारत के लघु एवं मध्यम उद्योगों को मिलना चाहिए। इस दिशा में बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने आगे कहा, इस बजट में नारियल, कोको, काजू और चंदन की खेती करने वाले किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। विभिन्न राज्यों को मजबूत करके, यह बजट संतुलित और समान विकास की नींव रखता है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कई प्रमुख पहलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देने से राज्यों का विकास होगा। उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में कई प्रमुख पहलें शामिल की गई हैं। इनमें समर्पित माल ढुलाई गलियारों का विकास, राष्ट्रीय जलमार्गों का विस्तार, हाई-स्पीड रेल गलियारों का निर्माण और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देना शामिल है। इसके अलावा, नगर निगम बांडों को बढ़ावा देने का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करना है। ये सभी उपाय मिलकर विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देंगे।

खरगे ने पूछा- कहां है मेक इन इंडिया ?

किसान भी बेहाल, बजट 2026 को बताया दिशाहीन

नई दिल्ली।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश की गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मेक इन इंडिया कहां है और दावा किया कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13फीसदी पर अटकी हुई है। खरगे ने किसानों के लिए समर्थन की कमी पर भी निराशा व्यक्त की और कहा कि वे अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका उल्लेख नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे हैं।

बजट2026 भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। मिशन मोड अब चुनौती मार्ग बन गया है। सुधार एक्सप्रेस शायद ही किसी सुधार जंक्शन पर रुकती है। नतीजा- कोई नीतिगत दूरदृष्टि नहीं, कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं। हमारे अन्नदाता किसान अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों का और अधिक अध्ययन करना होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य सरकारों को कोई राहत प्रदान करती हैं। संघवाद को भारी नुकसान हुआ है। क्या गायब है और कहां मायने रखता है- विनिर्माण- कोई पुनरुद्धार रणनीति नहीं; 13% पर अटका हुआ है। मेक इन इंडिया कहां है? इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष ने गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को राहत प्रदान करने में सरकार की विफलता की आलोचना की और वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। खरगे ने रोजगार

> **मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश की गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है।**

सृजन और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किसी गंभीर योजना के अभाव और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर ठोस घोषणाओं की कमी का भी दावा किया, साथ ही एमजीएनआरईजीए की जगह लागू किए गए नए कानून के लिए किसी आवंटन का उल्लेख न होने की बात भी कही। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2026 भाषण पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वित्त मंत्री का भाषण आम आदमी के हितों और देश के विकास पर केंद्रित था।

अर्थव्यवस्था को जहर दिया जा रहा, राहुल ने संघ और बीजेपी पर साधा निशाना; कहा- समाज को बांट रहे

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-2027 की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह भारत के वास्तविक संकटों को नजरअंदाज करता है और सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाता। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं और घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि किसान संकट में है। राहुल गांधी ने कहा कि युवा बेरोजगार हैं। विनिर्माण क्षेत्र गिर रहा है। निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं। घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। किसान संकट में है। वैश्विक संकटों का खतरा मंडरा रहा है - इन सब की अनदेखी की जा रही है। एक ऐसा बजट जो सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाता, भारत के वास्तविक संकटों को नजरअंदाज करता है। केंद्रीय बजट रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट को फीका बताया। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि हालांकि दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है, लेकिन 90 मिनट के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट 2026/27 इसके प्रचार के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से नीरस था। भाषण भी अपारदर्शी था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बजट में देश की गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे हैं और बजट 2026 भारत की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई एक समाधान नहीं देता है।

दिशाहीन, इसमें कुछ नहीं है, बंगाल को आवंटन में नजरअंदाज किया- ममता बनर्जी का तीखा रिएक्शन

बंगाल। बजट पेश होने से पहले, आम आदमी से लेकर बाजार विशेषज्ञों तक, सभी के मन में कई तरह की अपेक्षाएं होती हैं। लोक लुभावनी घोषणा का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश का आम बजट पेश किया। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने बजट की सराहना की और इसे दूरदर्शी बताया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे दिशाहीन बताया। केंद्रीय बजट 2026-27 दिशाहीन है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव है और बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इसमें शिक्षा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया है और इसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। उन्होंने केंद्र पर जानबूझकर पश्चिम बंगाल को आवंटन में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा को आगामी विधानसभा चुनावों में हार की आशंका के चलते राज्य को दरकिनार किया गया है।

भाजपा का बजट सिर्फ पांच प्रतिशत लोगों के लिए : अखिलेश यादव

लखनऊ। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट में आई गिरावट को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था, सवाल यह नहीं है कि बाजार कब खुलेगा, सवाल यह है कि और कितना गिरेगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से भी क्या अपेक्षा की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का हर बजट 1/20 का बजट होता है, क्योंकि यह केवल 5 प्रतिशत लोगों के हित में तैयार किया जाता है।

उन्होंने कहा कि यह बजट अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का दस्तावेज है तथा इसे भाजपाई भ्रष्टाचार की अदृश्य खाता-बही बताया। सपा अध्यक्ष का कहना है कि इस बजट में न आम जनता का जिक्र है और न ही उनकी फिक्र। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बेतहाशा बढ़ती कीमतों के बावजूद आम लोगों को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई, जो सीधे तौर पर टैक्स-शोषण है। वहीं दूसरी ओर अमीरों के कारोबार और घूमने-फिरने पर कई तरह की छूटें दी गईं, जबकि बेकारी और बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं व आम नागरिकों की उम्मीदों की थाली खाली रह गई। उन्होंने बजट को निराशाजनक और निंदनीय बताते हुए कहा कि यह आम आदमी की जरूरतों से पूरी तरह कटा हुआ है।

ट्रॉफी चोर नकवी की नई चाल, टी20 विश्वकप में खेलेगा पाकिस्तान; भारत के साथ मैच का करेगा बहिष्कार

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप 2026 से पहले पाकिस्तान का ड्रामा जारी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टूर्नामेंट में खेलने का फैसला किया है लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत के मुकाबलों का बहिष्कार करेगी यानी भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान की टीम शामिल नहीं होगी। पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान टीम को आगामी विश्व कप के लिए श्रीलंका की यात्रा की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। बयान में इस फैसले की कोई वजह नहीं बताई गई।

नकवी ने की थी शहबाज शरीफ से मुलाकात

इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और उन्हें बांग्लादेश विवाद की पूरी जानकारी दी थी। इसके बाद उन्होंने 2 फरवरी तक फैसला लेने की बात कही थी। बड़े दावे करने वाले पाकिस्तान ने औंधे मुंह गिरकर अब टी20 विश्व कप में खेलने का फैसला लिया है। हालांकि, उनकी टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेले जाने वाले मैच में नहीं शामिल होगी।

बांग्लादेश विवाद में पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई?

पाकिस्तान का ड्रामा बांग्लादेश विवाद के साथ ही शुरू हुआ। पाकिस्तान खुलकर बांग्लादेश की मांग के समर्थन में उतरा था। आईसीसी ने जब बांग्लादेश की मांग को लेकर बोर्ड की बैठक में वोटिंग कराई तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के पक्ष में वोट दिया। पाकिस्तान का यह कदम भी बांग्लादेश के काम नहीं आ सका और आईसीसी ने अंत में बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बांग्लादेश के बाहर होने से पाकिस्तान बौखला गया और उसने आईसीसी पर पक्षपात का आरोप लगाया। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा कि उनकी टीम का खेलना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के फैसले पर निर्भर है। नकवी ने कहा कि वह अपनी सरकार के फैसले को मानेंगे और उसी के अनुसार विश्व कप में खेलने पर फैसला लेंगे। इसके बाद नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और बयान आया कि फैसला सोमवार (2 फरवरी) तक लिया जाएगा। रविवार यानी 1 फरवरी को पाकिस्तान की सरकार ने सोशल मीडिया पर टी20 विश्व कप के लिए टीम भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान की सरकार ने यह भी फैसला लिया कि भारत के खिलाफ खेले जाने वाले 15 फरवरी के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी।

ग्रुप ए में पाकिस्तान

पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के साथ शामिल है। वह अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, जो इस टूर्नामेंट का भारत के साथ सह-मेजबान है।

पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को टी20 विश्व कप के उद्घाटन दिन नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद 10 फरवरी को अमेरिका से और 18 फरवरी को नामीबिया से मुकाबला करेगा। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करता है, तो उसे उस मैच के दो अंक गंवाने पड़ेंगे।

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं

*बजट 2026

नई दिल्ली।

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए आर्थिक विकास और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। विकसित भारत के संकल्प के साथ पेश किए गए इस बजट में सरकार ने जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार के ट्रेडर्स पर टैक्स की सख्ती की है। हालांकि, आम करदाताओं को विदेश यात्रा और पढ़ाई के मामले में बड़ी राहत दी गई है।

1. शेयर बाजार-

शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए बजट में झटका लगा है। सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) बढ़ा दिया है

फ्यूचर्स -STT 0.02फीसदी से बढ़ाकर 0.05फीसदी कर दिया गया है।

ऑप्शंस - STT 0.1फीसदी से बढ़ाकर 0.15फीसदी कर दिया गया है।

2. विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टीसीएस घटा

मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज और शिक्षा/चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे (एलआरएस) पर टीसीएस (टीसीएस) की दर को घटाकर 2फीसदी कर दिया है। पहले यह दरें काफी ऊंची (5फीसदी से 20फीसदी तक) थीं।

3. इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च

सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। वित्त वर्ष 2015 में यह मात्र 2 लाख करोड़ रुपये था, जो अब छह गुना बढ़ चुका है।

4. राजकोषीय घाटा का लक्ष्य

सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3फीसदी तय किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों (आई) में यह 4.4फीसदी आंका गया है।

5. एसएमई के लिए 10,000 करोड़ का फंड छोटे उद्योगों को चैम्पियन बनाने के लिए तीन आयामी रणनीति अपनाई गई है। सरकार ने एक समर्पित 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की है। साथ ही, TReDS प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी दिया जाएगा।

6. शेयर बायबैक पर टैक्स नियम बदला

कंपनियों द्वारा शेयरों के बायबैक से होने वाली आय को अब शेयरधारकों के हाथों में कैपिटल गेन्स माना जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स लगेगा।

7. इंडस्ट्री और इनोवेशन- सेमीकंडक्टर और बायो-फार्मा

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 और बायो-फार्मा शक्ति (बायो फार्मा) जैसी नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। साथ ही, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए भी एक विशेष स्कीम लाई जाएगी।

8. कैंसर की दवाएं और कस्टम ड्यूटी

स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने के लिए कैंसर के मरीजों के लिए 17 दवाओं और औषधियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।

इसके अलावा, सोलर ग्लास और लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर भी कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है।

9. विदेशी संपत्ति का खुलासे के लिए छह महीने का मौका

छोटे करदाताओं के लिए एकमुश्त विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना (फॉरेन असेट डिक्लेरेशन स्कीम) लाई जाएगी, जो छह महीने के लिए खुली रहेगी। इसके अलावा, 20 लाख रुपये से कम की अचल विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर अब मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

10. कृषि और मत्स्य पालन

मछुआरों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय जहाजों द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पकड़ी गई मछलियों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की योजना भी बनाई गई है।

बजट 2026-27 स्पष्ट रूप से युवा शक्ति और उत्पादन क्षमता पर केंद्रित है। जहां स्टब्ब में बढ़ोतरी से बाजार में उतार-चढ़ाव दिख सकता है, वहीं टीसीएस में कटौती और कैपेक्स में वृद्धि से अर्थव्यवस्था के पहियों को गति मिलने की उम्मीद है।